आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरुवार 12.03.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में रखा विकास कार्यों का लेखा जोखा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा – राज्यपाल के अभिभाषण में कोई नया विजन नहीं है।
- केंद्र सरकार ने कहा– देश में कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है और अब इसके आयात का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा होर्मुज जलडमरू–मध्य के बाहर से आ रहा है।
- प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं, अफवाहों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश।
- प्रदेश में पीएमजीएसवाई पहले चरण के तहत अधूरी सड़कों को पूरा करने की समय सीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ी।

मुख्यमंत्री

भराड़ीसैंण में राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कल राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा सदन के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार "विकल्प रहित संकल्प" के साथ उत्तराखंड को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

वहीं, बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में कोई नया विजन नहीं है और पुराने बिंदुओं को जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को 2047 तक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य तो घोषित किया गया है, लेकिन इसके लिए स्पष्ट रोडमैप दिखाई नहीं देता। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस का विरोध और बहिर्गमन कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रदेश की समस्याओं को लेकर उनकी पीड़ा का प्रतीक है।

मिनी स्टेडियम

38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के बाद प्रदेश सरकार अब जमीनी स्तर पर खेल सुविधाओं के विस्तार में जुट गई है। बजट सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन को बताया कि प्रदेश के हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जमीनी स्तर पर खेल मैदान और मिनी स्टेडियमों के निर्माण से युवाओं को खेल में रुचि बढ़ाने और खेल प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी। इस योजना को लागू करने के लिए प्रशासन स्तर पर कार्यवाही जारी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 103 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। इस आयोजन के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर का आधारभूत खेल ढांचा विकसित किया गया और सरकार ने इसे लेगेसी पॉलिसी के तहत खेल अकादमी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया है, ताकि खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण मिल सके। इस संबंध में खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम के लिए औसतन एक दशमलव 1–8 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है और इसके निर्माण के लिए एक करोड़ 70 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने यह कहा कि अब तक 102 मिनी स्टेडियम बनाए जा चुके हैं, जबकि छह निर्माणाधीन और 11 प्रस्तावित हैं।

बजट सत्र

राज्य विधानसभा के बजट सत्र में कल सदन में गैरसैंण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने–सामने दिखे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सदन में कहा कि भराड़ीसैंण, गैरसैंण, प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। साथ ही पूरे गैरसैंण और आसपास के क्षेत्रों को पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पर्यटन मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई को लेकर उनके बयान को तोड़–मरोड़कर पेश किया गया है और विकास के नए आयामों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। वहीं बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने सदन में गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किए जाने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में गैरसैंण को लेकर सरकार का स्पष्ट विजन नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि गैरसैंण राज्य आंदोलन की भावनाओं से

जुड़ा विषय है और इस पर ठोस रोडमैप पेश किया जाना चाहिए, न कि केवल औपचारिक घोषणाएं की जाएं। सदन में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली।

कच्चे तेल आपूर्ति

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है और देश के कच्चे तेल के आयात का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा अब होर्मुज जलडमरू–मध्य के बाहर से आ रहा है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया संघर्ष पर अंतर मंत्रालयी बैठक में सुश्री सुजाता ने कहा कि सरकार के पास सुरक्षित कच्चे तेल की मात्रा होर्मुज जलडमरूमध्य से आने वाली मात्रा से अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से घरेलू एलपीजी उत्पादन 25 प्रतिशत बढ गया है।

ईंधन

प्रदेश में एलपीजी और ईंधन आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भराडीसैंण में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सभी प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के राज्य स्तरीय समन्वयक और अन्य संबंधित अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को अफवाहों पर कड़ी नजर रखने और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए। इसके लिए जिलों में नियमित रूप से छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव ने तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में क्विक रिस्पॉन्स टीम गठित करने के निर्देश दिए। यह टीम गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी या अवैध स्टॉकिंग करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेगी। बैठक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के राज्य स्तरीय समन्वयक कृष्ण कुमार गुप्ता और स्वर्ण सिंह ने बताया कि राज्य में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गैस आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है।

पीएमजीएसवाई

केंद्र सरकार ने प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण के अंतर्गत अवशेष सड़कों को पूरा करने की समय सीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इस अपर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से उत्तराखंड राज्य को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पीएमजीएसवाई के पहले चरण के तहत लगभग 55 अधूरे कार्यों को पूरा करने का वित्तीय भार राज्य सरकार को वहन करना प्रस्तावित था। अब केंद्र सरकार के निर्णय के बाद यह राशि केंद्र व राज्य के बीच 90 और 10 के अनुपात में खर्च की जाएगी। इससे प्रदेश सरकार पर पड़ने वाला वित्तीय भार काफी कम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में सहायता मिलेगी। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क और विकास को नई गति मिलेगी, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर.....

ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में संचालित उत्तराखंड बजट सत्र को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है– नवोदय टाइम्स मुख्यमंत्री धामी के हवाले से लिखता है– विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य कर रही सरकार। इस खबर पर दैनिक जागरण का शीर्षक है– आने वाले पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड देने का है संकल्प।

वन भूमि पर बसे लोगों को मिलेगा भूमिधरी अधिकारी– इस शीर्षक के साथ हिन्दुस्तान लिखता है– उत्तराखंड में दशकों से वन भूमि पर रहने वालों को भूमिधरी अधिकार दिया जाएगा।

पश्चिम एशिया में जंग के कारण देश में ऊर्जा संकट पर दैनिक जागरण प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से लिखता है– घबराने या अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। रसोई गैस किल्लत पर हिन्दुस्तान का शीर्षक है– सरकार ने कहा, रिफाइनरियों ने उत्पादन में 25 फीसदी तक बढ़ोतरी की। इस खबर पर अमर उजाला लिखता है– गैस किल्लत में बिजली की मांग बढ़ेगी, यूपीसीएल ने शुरू की तैयारी।

इच्छामृत्यु को पहली सुप्रीम अनुमति – इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण लिखता है– 13 वर्ष से कोमा में पड़े हरीश की हटाई जा सकेगी जीवन रक्षक प्रणाली।